



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Ho 421

नई दिल्ली, शनिवार, श्रवतूबर 17, 1987 (आश्विन 25, 1909)

No. 42]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17, 1987 (ASAVINA 25, 1909)

इस माण में फिल्म पृष्ठ र्राया की जाती है जिससे कि यह असग संकलन के कप में क्या का सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

## भाग 111-खण्ड 4

# [PART III—SECTION 4]

विधिक किकायों द्वारा कारी की गई दिविद अधिसूचन।एं जिस्मे कि आदेश, विज्ञादन और सूचना सम्मिलत हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय शहरी बैंक विभाग

"दि श्रार्केंड", विण्य व्यापार केन्द्र

बम्बई-400005, दिनांक 25 सितम्बर 1987

संदर्भ: यू० बी० डी० सं० श्रार० ई० एव० 192/डी० 4-(268)-85/86--बैंककारी विनियमन श्रिधिनियम, 1949 की धारा 56 के खण्ड (थथ) के साथ पठित धारा 24 क द्वारा प्रदत्त भिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतदबारा यह घोषित करना है कि उक्त श्रिधिनयम की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 श्रीर 24 के प्रावधान विक्रम को०-श्रापरेटिव बैंक लि०, श्रहमदाबाद पर काल्पुर कर्माण्यल को०-श्रापरेटिव बैंक लि० से उसके बारा लिए गए उधारों संबंधी देयनाश्रों के मामले में दिनांक 30 जून, 1988 तक लागू नहीं होंगे।

बी० एल० जैन, मुख्य भ्रधिकारी मोरियन्टल बैंक म्रॉफ कॉमर्स (कार्मिक विभाग) प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 ग्रगस्त 1987

सं० 3901—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का ग्राधिग्रहण ग्रीर ग्रन्तरण) ग्राधिनियम 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदक्ष ग्राक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रोरियन्टल बैंक ग्रॉफ कॉमर्स का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ग्रीर केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ग्रोरियन्टल बैंक ग्रॉफ कॉमर्स (ग्राधिकारी) सेवा विनियम 1982 में ग्रीर ग्रागे संशोधन करने के लिए, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

- 2. संक्षिप्त शीर्षक श्रीर प्रारम्भ :--(1) इन विनियमों का नाम श्रीरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (श्रीधकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1982 होगा ।
- (2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाणित होते की तारीख से लागू होंगे ।
- 3. वितियम 5 में संशोधन
- (I) विनियम 5 (1) के भ्रन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया समझा जाए :—"परन्तु 1-1-1985 की भौर इस

1-289 GI/87

तारीख से, किनष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-I ग्रीर मध्यम प्रबंध ग्रेड स्केल-II ग्रीर III के न श्रिधकारियों को, जो श्रपने वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हों, उनके स्केल की उच्चतम सीमा पर पहुंचने के बाद मेवा के प्रत्येक 5 वर्ष पूरे करने पर, श्रन्तिम वेतनबृद्धि के बराबर पदोन्नित श्रवरोध वेतनबृद्धियां दी जाएंगी जो किनष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-I के श्रिधकारियों के लिए ऐसी दो वेतन बृद्धियों श्रीर मध्यम प्रबंध ग्रेड स्केल II श्रीर III के श्रिधकारियों के लिए ऐसी एक वेतनबृद्धि से ग्रिधक नहीं होगी।

ऐसे अधिकारियों के मामले में, जिन्होंने अपने वेतनमान की उच्छतम सीमा पर 5 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली हो, ऐसी पहली पदीन्ति अवरोध वेतन वृद्धि देय तारीख से या 1 जनवरी, 1985 से, जो भी बाद में हो, दी जाएगी, परन्तु ऐसी दूसरी वेतनवृद्धि उन पात अधिकारियों को दी जाएगी जो 1 जनवरी, 1987 से पहले पात न बने हों।"

(II) विनियम 5 (2) के श्रन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया समझा जाए:---

"परन्तु.1-2-1984 को और इस तारीख से, जो ग्रिधिकारी ग्रपने वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हों, उन्हें वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हों, उन्हें वेतनमान की उच्चतम सीमा पर एक वर्ष पूरा करने के बाद सी०ए० ग्राई० ग्राई०बी० परीक्षा का भाग-। उत्तीर्ण करने के लिए 100/- रुपए प्रतिमाह ग्रोर वेतनमान की उच्चतम सीमा पर दो वर्ष पूरे करने के बाद सी० ए० ग्राई० ग्राई० बी० परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने के लिए 200/- रु० प्रतिमाह का व्यावसायक योग्यता भत्ता दिया जाएगा।

विनियम 22 में संशोधन

विनियम 22 (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जाए —

1-2-1984 को श्रीर इस तारीख से, जहां किसी श्रिधकारी को बैंक द्वारा श्रावासीय सुविधा नहीं दी गई हो, तो वह, जिस वेतन-मान में उसे रखा गया है, उसे वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन के 10% से श्रिधिक राणि, जो उसके द्वारा श्रावास देतु वस्तुत: प्रदत्त की गई हो, के बराबर राणि का मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा। यह राणि निम्नलिखित दरों के तहत दी जाएगी:---

जहां कार्यस्थल निम्नजिखित में से एक	देय मकान किराया	
हो	भत्ता	
	2	
<ol> <li>सरकार के मार्गनिर्देशों के भ्रनुसार मण्डल ढारा समय-समय पर विनि- दिख्ट किए गए ''क'' श्रेणी के शहर श्रौर समूह ''क'' के परियोजना क्षेत्र के केन्द्र</li> </ol>	मूल वेतन का 17∄% परन्तुं श्रधिकतम 500 - रु० प्रतिमाह	
<ol> <li>उपर्युक्त (।) में सम्मलित न किए</li></ol>	मूल वेतन का 15%	
गए क्षेत्र- । ग्रीर समूह "ख" के	परन्तु ग्रिधकतम	
परियोजना क्षेत्र के केन्द्र	400/-मञ्जितमाह	

3. क्षेत्र-ा। श्रौर राज्य राजधानियां श्रौर संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियां जो ऊपर (1) श्रौर (11) में शामिल नहीं हों	मूल वेतन का $12\frac{1}{2}\%$ यरन्तु, श्रधिकतम 300-80 प्रतिमाह
4. क्षेत्र-III	मूल वेतन का 10% परन्तु भ्रष्टिकतम 250/-रु० प्रतिमाह

1

टिप्पणी : उपर्युक्तानुसार मकान किराया भत्ता किराए की रसीदें प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा । इसके अलावा, अधि-कारी प्रमाण-पत्न के आधार पर भी उपयुक्त दरों पर मकान किराए का दावा कर सकता है जो अधिकतम मकान निम्नानुसार होगा:—

प्रमुख ''क'' श्रेणी के शहर एव समूह ''क'' के परियोजना क्षेत्र के केन्द्र	ग्रधिकतम 275/-रु०
क्षेत्र-I के धन्य स्थल ग्रीर समूह ''ख'' के परियोजना क्षेत्र के केन्द्र	ग्रधिकतम 225/- <b>घ</b> ०
क्षेत्र-II ग्रौर राज्य राजधानियों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियां	श्रधिकतम 165/-रु०
क्षत्र-IH	110/-रु० (निश्चित)

विनियम 23 में संशोधन

(I) विनियम 23 (IV) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित साझा जाए :—

"1-1-1987 को और इस तारीख से, यंदि कोई ग्रधिकारी गैंक्षणिक वर्ष के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान तित कर दिया जाए और यदि उसके एक या एक से ग्रधिक बच्चे पिछले स्थान पर स्कूल या कालेज में पढ़ रहे हों, तो गैंक्षणिक वर्ष के बीच स्थाना-तिरत होने पर उसे 150/- क० प्रतिमाह का भत्ता, दूसरे स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से गैंक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक सभी बच्चों के लिए दिया जाएगा परन्तु, सभी बच्चे पिछले स्थान पर श्रपनी पढ़ाई बन्द कर दें तो उस स्थात में वह भत्ता बन्द कर दिया जाएगा।"

( $I^1$ ) विशियम 23 (VI) निम्त्रलिखित द्वारा प्रतिस्था- पित समझा जाए :—

"1-1-1985 को श्रौर इस तारीख से, यदि उससे एक बार कम से कम 7 दिन के लिए किसी उचतर स्केल के किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कराया जाए तो यह श्रपने मूल वेनन के 10% के बराबर स्थानापन्न भक्ता पाने का हकदार होगा जो उस श्रवधि के

लिए अधिकतम 250/-रु० प्रतिमाह होगा जिसके लिए उसने स्थाना-पन्न रूप से कार्य किया हो । स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए वेतन माना जाएगा किन्तु भ्रन्य प्रयोजनों के लिए नहीं ।

परन्तु, यदि कोई श्रधिकारी विनियम 6 के अन्तर्गत एकमान्न पदों के वर्गीकरण के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्त रूप से कार्य करने के लिए आता है तो जिसतारीख को वर्गीकरण का पुनरीक्षण किया जाएगा, उस तारीख से वह एक वर्ष की श्रवधि तक स्थानापन्त भसे का पात नहीं होगा।"

(111) विनियम 23~(X) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित समज्ञा जाए :—

"1-1-1985 को और इस तारीख़ से, यदि वह नीचे सारणी के कालम-1 में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है तो उस स्थान के लिए उस सारणी के कालम-2 में उल्लिखित दर पर पहाड़ एवं इंधन भत्ता :—

#### सारणी

स्थान	<b>द</b> र
जो म्रधिकारी माध्य समुद्री सतह से ऊपर 1500 मीटर श्रौर इससे श्रधिक ऊँचाई पर हों	वेतन का 10% परन्तु, म्रधिकतम 130/-रुऽ प्रतिमाह
जो श्रधिकारी माध्य समुद्री सतह से ऊपर 1000 मीटर श्रीर इससे श्रधिक परन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर हों	वेतन का 8% परन्तु ग्रधिकतम 100/- र∘प्रतिमाह

## विनियम 42 में संशोधन

(I) विनियम 42 (2) (II) निम्नलिखित द्वारा प्रति-स्थापित समझा जाए :—

"1-1-1987 को न्प्रौर इस नारीख से, यदि पूरे माल डिब्बे का पान प्रधिकारी, रेलवे द्वारा दी जाने वाली "डिब्बा सेवा" की मुविधा का लाभ उठाता है, तो किन्छ या मध्यम प्रवंध ग्रेड में होने पर उसे एक डिब्बे के भौर यदि वह वरिष्ठ या सर्वोच्च प्रबंध ग्रेड के हैं तो उसे दो डिब्बों के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि रेल द्वारा सम्बद्ध दो स्थानों के बीच सामान सड़क परिवहन द्वारा ले जाया जाता है तो बिल प्रस्तुत किए जाने पर वास्तविक माल भाडे की प्रतिपूर्ति की जाएगी बगर्त कि यह खर्च माल को रेल-गाड़ी द्वारा ले जाए जाने पर श्रनुमत्य श्रधिकतम मात्रा पर श्राने वाले खर्च से प्रधिक नहो । यदि तैनाती के पिछले या नए स्थान पर रेलवे स्टेशन या रेलवे से सम्बद्ध एजेन्सी न हो तो अधिकारी को निकटतम रेलवे स्टेशन या रेलवे से सम्बद्ध एजेन्सी तक सड़क द्वारा सामान से जाने के लिए वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाएगा यदि दोनों ही स्थानों पर रेलवे स्टेशन या रेलवे से सम्बद्ध एजेन्सी न हो तो श्रधिकारी को किसी अनुमोदित परिवहन प्रचालक द्वारा निर्धारित भार तक का सामान सड़क से ले जाए जाने पर किया गया वास्तविक खर्च दिया जाएगा।

(II) विनियम 42 (3) निम्न से प्रतिस्थापित समझा जाए:—

"1-1-1987 को तथा इस तारीख से स्थानान्तरित होने पर श्रिधकारी, पैकिंग, स्थानीय परिवहन तथा सामान के बीमा श्रादि के संबंध में किए गए खर्चों के लिए नीचे दिए अनुसार एक-मुण्त राशि प्राप्त करने का पात होगा।

ग्रेड	एक मुक्त राशि
सर् <del>वोच्च</del> प्रबंध वर्ग तथा वरिष्ठ प्रबंध वर्ग	1500/- হ৹
मध्यम प्रबंध वर्ग तथा कनिष्ठ	1000/- ৰ্
प्रबंध वर्ग	-

विनियम 24 में संशोधन

विनियम 24(1) (ख)मे खंड (IV) के पण्चात खण्ड (V) निम्तानुसार जोड़ा जाए :—

"1-1-1987 को तथा इसी तारीख में जहा मान्यताप्राप्त ग्रस्पताल प्राधिकारियों तथा बैंक का चिकित्सा ग्रधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि निम् लिखित बीमारियों के संबंध में, जिल्में श्रस्पताल में रह कर उपचार करवाए जाने की ग्रावश्यकता है किए गए खर्च को ग्रस्पतालीकरण व्यय माला जाएगा ग्रीर ग्रधिकारी के मामले में 75% तक तथा उसके परिवार के सदस्य के मामले में 50% तक के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी :--

कैन्सर, तपेदिक, लकवा, हृदयरोग, रसौली, चेचक, प्लूरिसी, डिप्थिरिया, कुष्ठ रोग, गुर्दे की बीमारी ।

विनियम (44) में संशोधन

विनियम  $44(^{11})$  निम्िं से प्रस्थापित समझा जाए :—-

"1-1-1987 को तथा इस तारीख से चार वर्ष में एक बार जब कोई प्रधिकारी छुट्टी याता रियायत लेता है तो उसे एक बार में प्रधिकतम एक महीने की प्रपनी साधिकार छुट्टी छोड़कर उसके बदले धन लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, छुट्टी के बदले कोई धन के प्रयोजनार्थ, उस माह के लिए देय सम्पूर्ण परिलिख्यां प्रनुमत्य होंगी जिसके लिए छुट्टी याता रियायत दी गई हो।"

परन्तु किसी अधिकारी को प्रधानमंत्री राहत निधि में दान करने हेतु अपनी एक दिन की साधिकार छुट्टी के बदले धन लेने की अनुमति दी जाएंगी बशर्ते कि वह बैंक को इस आश्रय का पत्न दे जिसमें उक्त राशि इस निधि में भेजने के लिए बैंक को प्राधिक्षत किया गया हो।"

> ग्रो० पी० महाजन, मुख्य प्रवंधक (कार्मिक)

दी इन्स्टीट्यूट श्रांफ़ चार्टर्ड एकोजन्टन्ट्स ऑफ इन्डिया

## नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1987

# (चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० नं०-3-सी० सी० ए० (8)/ 8/87-88--रेगूलेशन 10(1) की धारा (2) चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगूलेशन 1964 के अनुसार एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि असावधानी के कारण श्री अशोक सिब्छी (सदस्यता सं० 72319), 18131, कौशलपुरी, बम्बा रोड, कानपुर-208012 को जारी किया गया कार्य करने का प्रमाण पन्न दिनांक 28 जुलाई, 1986 से रह किया गया है।

## दिनांक 25 मितम्बर 1987

## शुक्ति पत

सं० 3-ई० सी० ए० (5)/7/87-88—निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न कराने के कारण दिनांक 1-8-1986 से नाम हटाने के लिए जारी की गई प्रधिसूचना नं० 3-ई० सी० ए० (4)/10/86-87 दिनांक 27-2-1987, जिसमें श्री प्रबीर कुमार दास (सदस्यता संख्या 13618), 309, बी० बी० गांगुली स्ट्रीट, कसकता-700012, का नाम कमांक 18 पर लिखा गया था, श्रब हटाया हुम्रा माना जाए। इसके फलस्वरूप श्री प्रबीर कुमार दास का नाम बिना किमी विवधान के दिनांक 1 श्रगस्त, 1986 से संदस्यता रजिस्टर में निरन्तर जारी माना जाए।

मं० 3-ई० मी० ए०(5)/8/87-88---निर्धारित सदस्यता मुल्क जमा न कराने के कारण दिनांक 1-8-1981 से नाम हटाने के लिए जारी की गई प्रशिक्ष्मचना नं० 4-ई० मी० ए० (3)/82-83 दिनांक 13-8-1982, जिंधमें श्री एन० एन० किनी (सदस्यता मंख्या 15769), 75-बी, स्तीश मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700026, का नाम क्रमांक 2 पर लिखा गया था, श्रब हटाया हुआ माना जाए। इसके फलस्वरूप श्री एन० एन० किनी का नाम बिना किसी विवधान के दिनांक 1 अगस्त, 1981 से स्दस्यता रजिस्टर में निरन्तर जारी माना जाए।

भ्रार० एल० चोपड़ा संचिव

## मदास, दिनांक 18 क्षितम्बर 1987

# (चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-एम० सी० ए० (8)/4/87-88— चार्टर्ड प्राप्त सेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्न उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए है क्योंकि वे श्रपने प्रैक्टिस प्रभाण **पत्र** को रखने के इच्छक नहीं है ।

ऋ० संख्या	सदस्यना संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	12935	श्री एम० वी टपाडे, एफ० सी० ए०, फाईनेन्स एग्जीकृटिव, केंसोराम- सीमेंट, बसन्तनगर— 505 187, करीमनगर डिस्ट० ए० पी०	1-4-1987
2.	15180	श्री० के० एस० सुन्दरा- राजन, एफ०सी०ए०, सेन्नेटरी, एणिया खोबाको- कं० लि०, 16/17, कालेज रोड, मद्रास600 006	28-6-1987
3.	18117	श्री पी० एम० कंडास्वामी, एफ० सी० ए०, 33, डा० रंगाचारी रोड, माइसापोर,	1-4-198
4.	21440	मद्रास-600 004 श्री एम० रामाभद्रन, ए०सी०ए०, 31, लोका स्कीम, 11 स्ट्रीट जवाहर नगर, सद्रास-600 082	30-6-198
5.	23168	श्री श्रार० श्रीनिवासन, ए०सी०ए०, 20/2, थिरूबेंगदम स्ट्रीट, राजा- श्रन्नामलाइ पुरम, मब्रास-600 028	30-7-198
6.	23510	श्री सी० श्रीनिवास, ए०सी०ए०,-एप० एम० सी०-4, वैस्ट मरेडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026	31-3-198
7.	24843	श्री ग्रार० वेंकटेश, ए०सी०ए०, 10, राधा- कृष्ना नगर मैन रोड, थिरूवनमियुर, मद्राप्त-600 041	1-4-198
8.	25043	श्री वाई० नागेस्वरा राव, ए०सी०ए०, एकाउन्टस- प्राफीसर, एफ० ए०जी०- बिल्म सैक्शन, ई०सी०- आई० एस०, ई० सी० प्राई० एस० पी०प्रो०, हैदराबाद-500 762	13-3-198

1	2	3	4.	1	2	3	4
9.	25079	श्री कें ० जी० मुरली, ए०सी०ए०, परोल जी०पी०एफ०, ग्रमार्टमेंटम, 5, फ्लोर पैट्रोलियम हाऊस, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम- कारपोरेशन लि०, 17,	4-5-1987	3.	23186	श्री संजय परेख, ए०सी०ए०, केयर भ्राफ श्री निर्मल कुमार परेख, डी०-308, सैक्टर 2बी, विधान नगर, दुर्गापुर-713 212	1-8-1986
10.	25904	जमशेदजी टाटा रोड, चर्च गेट, बम्बई-406 726 श्री रवि पडाकी,	1-7-1987	4.	23559	श्री एस० राघवन, ए०सी०ए०, एल०-23/3, सेन्द्रल एवेन्यू, कोराटटुर, मद्रास–600 080	1-8-1985
		ए०सी०ए०, एकाउन्टैन्ट, जौरी एग्रो कैमिकल्स लि०, जय किसान भवन, जौरी नगर,		5.	25085	श्री टी० रित्र, ए०सी०ए०, 19–सी, 10 ब्लाक, नवेली–607 801 ।	1-8-1987
11	26362	गोवा406 726 श्री ए० राजेन्द्रन, ए०सी०ए०, 62/2,	30-7-1987			अपृत	८० एस० चोपड़ा 'सचिव
		फकीर साहिब स्ट्रीट, सैकि॰ड लेम, ब्रिप्लीकेन, मद्राक्ष-600 005		<del></del>	नई	कमेचारी राज्य बीमा निगम दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर :	1987

ए०(8) 5/87-88—रेग्लेशन 10 सं० 3-एस० सी० (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकान्टेन्टस के रेगूलेशन 1964 के म्रिधिनियम 10(2)(बी०) के साथ पढ़ा जाए, के म्रनुसार एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण-पक्ष उनके श्राग दी गई तिथियों से रह समझे जाएेंगे क्योकि उन्होंने कार्यप्रमाण-पन्न हेतु वापिक गुरुक का भुगतान नहीं किया था।

'क∘ सं∘	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	272	श्री एस ० वेंकटाक्टप्तन, ए०सी०ए० , सी०-13, सन्धानी स्ट्रीट, सुक्रामनिया नगर, सेलम-636 005	1-8-1984
2.	20937	श्री एम० भ्रशोका, ए०सी०ए०, 32, वैस्ट- 350, साउथ साल्ट लेक- सिटी, उताह-84115-4414, (यू०एस०ए०)	1-8-1985

सं $\circ$  - यू- 16/53/86-चिकित्सा- 2(गुजरात)---कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक की निगम की णक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैटक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-83 द्वारा ये माक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा अष्टमदा-बाद के डा०एम०जे० पटेल को अहमदाबाद केन्द्र के लिए बीमा-कृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्न की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पन्न जारी करने के प्रयोजन के लिए 16-6-1987 से 30-6-1988 की अवधि तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में वर्तमान शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

सं० यू-16/53/86-चिकित्सा-2 (गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशकः को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध मे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैटक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के .आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23–5–83 द्वारा ये मक्तियां आगे मुझे सौंघी जाने पर मैं इसके ब्रारा डा०रजनीकान्त टाकुरदास मरफतिया, गायत्नी अपार्टमेंट, 10/411, गाधी चौक, सूरत-395003 को गुजरात राज्य के सूरत क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्न की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पन्न जारी करने के

प्रयोजन के लिए दिनांक 19-8-87 से 30-6-1988 तक के लिए, अथवा पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, वर्तमान गर्ती पर ६० 750/- प्रतिमास के पारिश्रमिक पर, चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डा० वेद प्रकाश चिकित्सा आयुक्त

## एग्रर-इंडिया

## एभ्रर-इंडिया कर्मचारी सेवा यिनियम

एच० क्यू० 188-53 (सी०)—वायु निगम प्रधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 8 की (2) के साथ पठित धारा 45 द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए, एग्नर-इंडिया, केन्द्रीय सरकार के पूर्व प्रतुमोदन से एग्नर-इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम में संशोधन करने के लिए प्रागे निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

- इन विनिययों को एश्वर-इंडिया कर्मचारी सेवा (संगो-धन) विनियम, 1987 कहा जाएगा
  - 2. ये विनियम राजपल में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगें।
- एभ्रर्∽इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम, 1963 में (जो इसके बाद उक्त विनियम के रुप में) वर्तमान विनियम 48 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्था पित किया जाएगा।
  - (क) एक स्थायी कर्मचारी की सेवाएं बिना कोई कारण बताएं श्रीर बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं, बशर्ते कि सेवा विनियम 42 के श्रन्तर्गत दुराचरण का मामला न बनता हो ।
  - (i) यदि वह निगम की दृष्टि में (एश्चर-इंडिया के निदेशक मंडल) निगम की निरन्तर सेवा के लिए श्वक्षम श्रौर श्रयोग्य पाया/यी जाती/ती है श्रीर इस प्रकार उसकी श्रक्षमता श्रौर प्रयोग्यता के कारण उसका सेवा में बना रहना निगम के हित के लिए हानिकर है, ऐसी स्थित में भी उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

#### भ्रथवा

यदि निगम की दृष्टि में (एश्रर-इंडिया के निदेशक मंडल) उसका निरन्तर नीकरी में बना रहना निगम के हित के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करता है श्रीर उसके हित के लिए हानिकर है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

#### មមភា

यदि निगम की दृष्टि में (एश्रर-इंडिया के निदेशक मंडल) उसके ब्रारा किए जाने वाले कार्य में गोपनीयता का श्रभाव है तो निगम के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी सेवाग्रों को तत्काल समाप्त करना ग्रावण्यक होगा।

- (ख) परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवाम्रों को बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है, किंतु निगम उसे 38 दिन की लिखित सूचना दे सकती है या उसके बदले में पतन ।
- (ग) एक अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है, किंतु उसे 15 दिन की लिखित सूचना दे सकता है या उसके बदले में वेतन।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए वितन शब्द में सभी परिलब्धियां शामिल होंगी, जो उसे दी जाएंगी, यदि बह प्राधिकृत श्रवकाण पर है ।

- 3. विनियम 44 के बाद, उपयुक्त विनिययों में निम्निखित विनियम को जोड़ा जाएगा, ग्रथित—
- 44(क) इन विनियमों में किसी भी चीज के होते हुए और यिष निगम की दृष्टि में (एग्रर-इंडिया के निदेशक मंडल) इन विनियमों को प्रांसिंगक प्रावधानों के ग्रन्तर्गस जांच करना संभव अथवा व्यावहारिक नहीं है ग्रीर निगम यदि संतुष्ट है कि संबंधित कर्मचारी दुराचरण का दोशी है, ऐसे दुराचरण के लिए संबंधित कर्मचारी को विनियम 43 में उल्लिखित दण्ड में से कोई एक दंड दे सकती है।

इस भ्रसाधारण शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व बोर्ड संबंधित कर्मचारी को उसके दुराचरण के लिए 38 दिनों की पूर्व सूचना देगा श्रीर इस प्रकार के दुराचरण की आंच करना संभव या व्यावहारिक क्यों नहीं है भीर बोर्ड द्वारा दी गई मजा के कारण बताएगा भीर इस प्रकार की नोटिस के उत्तर में कर्मचारी को बोर्ड के समक्ष पूर्ण लिखित श्रभ्यावेदन देने का हक होगा।

(ii) इस विनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बोर्ड संबंधित कर्मचारी द्वारा धारा (i) के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना अविध के दौरान विए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं कर लेता।

टिप्पणी—मुख्य विनियम तारीख 19-10-1963 की ग्रिधि— सूचना द्वारा प्रकाणित । भारत सरकार का राजपत्न 1963, भाग III खण्ड VI पृष्ठ 636 ग्रीर 637।

> एस० नारायणस्वामी, सचित्र

## RESERVE BANK OF INDIA CENTRAL OFFICE

#### URBAN BANKS DEPARTMENT

#### "THE ARCADE" WORLD TRADE CENTRE

Bombay-400 005, the 25th September 1987

UBD. Reh. No. 192/D.4(268)-87,88.—In exercise of the powers conferred by Section 24A read with clause (qq) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Sections 81 and 24 read with Section 56 of the said Act shall not apply to the Vikram Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad upto 30 June, 1988 in respect of its borrowings from Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd.

B. L. JAIN Chief Officer

# ORIENTAL BANK OF COMMERCE (PERSONNEL DEPARTMENT) HEAD OFFICE

New Delhi-110 001, the 25th August 1987

No. 3901.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982.

- 2. Short title and commencement:— (1) These regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1982.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. Amendment to Regulation 5
- (i) At the end of Regulation 5(1) the following proviso be added:

"Provided that, on and from 1-1-1985 those officers in Junior Management Grade Scales I and Middle Management Grade Scales II and III who reach the maximum of their pay scale shall be granted stagnation increments equivalent to the last increment for every five completed years of service after reaching the maximum in the respective scales, subject to a maximum of two such increments for Officers in Junior Management Grade Scale I and one such increment for officers in Middle Management Grade Scales II and III. In case of those officers who have completed more than 5 years of service at the maximum of the respective scales the first such stagnation increment will be granted effective from the date on which it falls due or from 1st January, 1985 whichever is later, but the second such increment shall be granted to those eligible not earlier than 1st January 1987."

(ii) At the end of Regulation 5(2) the following proviso be added:

"Provided that, on and from 1-2-1984 those officers who have reached the maximum of their pay scales, professional qualification allowance of Rs. 100/- p.m. shall be granted for passing part I of C.A.I.B. Examination after they complete one year at the maximum in the scale of pay and Rs. 200/- p.m. both parts of C.A.I.B. Examination after they complete two years at the maximum in the scale of pay."

#### Amendment to Regulation 22

Regulation 22(2) may be substituted by the following: On and from 1-2-1984, where an officer is not provided with residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for house rent allowance being a sum equivalent to the

excess of the actual rent paid by him for his residential accommodation over 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, such sum being subject to the following rates:

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time by the Board in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	17-1/2% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 500/- p.m.
(ii) Area I not Covered by item (1) above and project area Centres in Group 'B'.	15% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 400/- P. M.
(iii) Area II and State Capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	12-1/2% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 300/- p. m.
(iv) Area III	10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- p. m.
Note: House Rent Allowance as above shall be paid on production of rent receipts, except that an officer may claim houserent allowance on certificate basis at the above rates subject to maximum as under:—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Major 'A' Class cities and project Area Centres In Goups 'A'	Maximum Rs.275/-
Other Places in Area I and project Area Centres In Group 'B'	Maximum Rs,225/-
Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories	Maximum Rs.165/-
Area III	Rs. 110/- (fixed)

Amendment to Regulation 23

(i) Regulation 23(iv) may be substituted by the following:

"On and from 1-1-1987, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, a mid-academic year transfer allowance of Rs. 150/- p.m. from the date he reports to the later place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children ease studying at the former place."

(ii) Regulation 23(vi) may be substituted by the following:

"On and from 1-1-1985, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 10% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purpose of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation taken effect."

(iii) Regulation 23(x) may be substituted by the following:

On, and from 1-1-1985, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a Hill

and Fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place:

TABLE

Place	Rates
1	2
Offices at altitudes of and over 1500 metres above Mean sea level	10% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-p.m.
Offices at altitudes of and over 1000 metres but below 1500 metres above Mean Sea level.	8% of pay subject to a maximum of Rs.100/-p.m.

Amendment to Regulation 24

In Regulation 24(1)(b), clause (v) may be added after clause (iv) as under:—

"On and from 1-1-1987, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domicilary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 75% in the case of an officer and 50% in the case of his family members:

Cancer, Tuberculosis, paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment."

#### Amendment to Regulation 42

(i) Regulation 42(2)(ii), may be substituted by the following:

"On and from 1-1-1987 if an officer eligible for full wagon avails of the facility of 'Container Service' by railways, he will be reimbursed actual charges for one container if he is in Junior or Middle Management Grade and for two containers if he is in Senior or Top Management Grade. If the baggage is transported by road between places connected by rail, the reimbursement will be limited to the actual freight charges against submission of bills subject to the cost not exceeding the cost of transport of the maximum permissible quantity by goods train. If there is no railway station or railway outagency at the old or new place of posting, the officer will be paid the actual cost of transporting the baggage by road up to the nearest railway station or railway-out-agency. If both the places do not have railway station/out-agency, the officer will be paid actual cost of transporting the baggage by road upto the stipulated weights by an approved transport operator."

(ii) Regulation 42(3) may be substituted by the following:

On and from 1-1-1987, an officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage etc.

Grade	1.ump Sum
Top Management & Senior Management	Rs. 1500/-
Middle Management and Junior Management	Rs. 1000/-

Amendment to Regulation 44

Regulation 44(ii) may be substituted by the following:

"On and from 1-1-1987 once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding one month at a time. For the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the

availment of the Leave Travel Concession commences shall be admissible.

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund."

O. P. MAHAIAN Chief Manager (Per.)

# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

# New Delhi-110002, the 18th September 1987 (Chartered Accountants)

No. 3CCA(8)/8/87-88.—In pursuance of Regulation 10(i) (ii) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued due to inadvertence to Shri Ashok Sabikhi (M. No. 72319), 118/131, Kaushal Puri. Bamba Road, Kanpur-208012 has been cancelled w.e.f. 28-7-1986.

### The 25th September 1987 CORRIGENDUM

No. 3ECA(5)/7/87-88.—In Notification No. 3ECA(4)/10/86-87 dated 27-2-1987 removing the names of Members with effect from 1-8-1986 on account of non-payment of prescribed membership fees, the name of Shri Prabir Kumar Das (M. No. 13618), 309, B. B. Ganguly Street, Calcutta-700012, included at S. No. 18 be treated as deleted. In consequence thereof the name of Shri Prabir Kumar Das continues to be borne on the Register of Members without any break effective from 1st August, 1986.

No. 3ECA(5)/8/87-88.—In Notification No. 4ECA(3)/82-83 dated 13-8-1982 removing the names of Members with effect from 1-8-1981 on account of non-payment of prescribed membership fees, the name of Shri N. N. Kini (M. No. 15769), 75-B, Satish Mukherjee Road. Calcutta-700026 included at S. No. 2 be treated as deleted. In consequence thereof the name of Shri N. N. Kini continues to be borne on the Register of Members without any break effective from 1st August, 1981.

R. L. CHOPRA Secretary

# Madras-600034, the 18th September 1987 (Chartered Accountants)

No. 3-SCA (8)/4/87-88.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	M, No.	Name & Address	Dates
1	2	2	4
1.	12935	Shri S. V. Tapade, F.C.A. Finance Executive Kesoram Cement Basantnagar 505187 Karimnagar Distt., A.P.	01-04-1987
2.	15180	Shri K.S. Sundararajan, F.C.A. Secretary Asia Tobacco Co. Ltd. 16/17, College Road, Madras 600006.	28-06-1987
3.	18117	Shri P. M. Kandaswamy, FCA 33, Dr. Rangachari Road Malapore Madras 600004,	01-04-1987

1			<sub>4</sub> -
4,	21440	Shri M. Ramabhadran, AAC 31, Loco Scheme II street-Jawahar Nagar Madras 6000082	30-6-1987
5.	23168	Shri. R. Shrinivasan, ACA 20/2, Thiruvengadam Street Raja Annamalai Puram Madras 600 028,	30-7-1987
6.	23510	Shri C. Srinivas, ACA SMC4 West Marredpally Secunderabad 500026	31-3-1987
7.	24843	Shri R. Venkatesh, ACA 10, Radhakrishna Nagar Main Road Thiruvanniyar Madras 600041	J-4-1987
8.	25043	Shri Y. Nageswara Rao,ACA Accounts Officer FAG-Bills Section ECIL-ECIL PO Hyde-abad 500762	13-3-1987
9.	25079	Shri II. G. Murali, ACA Payrell GPF Apart nent 51h F oor—Petrolet m House Hindustan Petrolet m Corpn. Ltd. 17, Jamshedji Tata Road Church gate Boml ay 400020	4-5-1987
10.	25904	Shri Kavi Padaki, ACA Accountant Zuari Agro Chemicals Ltd. Jai Kissan Bhawan Zuari Nagar Goa406726	1-7-1987
11.	26362	Shri A. Rajendran, ACA 62/2, Fakir Sahib Street Second Lane Triplicane Madras 600005	30-7 1987

No. 35CA(8)/5/8-88: In pursoance of Regulation 10 (1) (iv) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they had not paid their annual fees for certificate of practice.

S. No.	M. No.	Name & Address	Dates
J.	272	Shri S. Venkatakrishnan, ACA C-13, Sannadhi Street Subramania Nagar Salem-636005	1-8-1984
2.	20937	Shri M. Ashoka, ACA 32, West 350, South Salt Lake City UTAH 84115-4414 U.S.A.	1-8-1985
3.	23186	Shri Sanjay Parekh, ACA C/o Shri Nirmal Kumar Parekh D-308, Sector 2B Bidhan Nagar Durgapur 713212	1-8-1986
4-	23559	Shri S. Raghavan, ACA L-23/3, Central Axenue Korattur Madras 600080	1-8-1985
5.	25085	Shri T. Ravi ACA 19-C, 10th Block Neyveli 607801	1-8-1987

R. L. CHOPRA Secretary

#### EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 28th September 1987

No. U-16,53,86-Med-II(Guj),—In pursuance of the Resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951, conterring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. M. J. Patel, A/3, Woodland Apartment, Ahmedabad, to function as medical authority for areas in Ahmedabad centre with effect from 16-6-1987, for a further period upto 30-6-1988, or till a Full-Time Medical Referee joins, whichever is earlier, on the existing terms and conditions, for the purpose of medical examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of original certificates is in doubt.

No. U. 16/53/86-Med-II(Guj.).—In pursuance of Resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. Rajnikant Thakardas Marfatia, Gayatari Apartment, 10/411, Gandhi Chowk, Surat-395003, to function as medical authority for Surat Centre in Gujarat with effect from 19-8-1987, for a further period upto 30-6-1988, or till a Full Time Medical Referce joins, whichever is earlier, on the existing terms and conditions, at the rate of Rs. 750/- per month consolidated, for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. VED PRAKASH Medical Commissioner

#### AIR INDIA

### AIR-INDIA EMPLOYEES SERVICE REGULATION

HQ/100-53(C).—In exercise of the powrs conferred by Section 45, read with sub-section (2) of Section 8 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), Air-India, with the previous approval of the Central Govrnment, hereby maks the following Regulations further to amend the Air-India Employees' Service Regulations, namely:—

- 1. (i) These Regulations shall be called the Air-India Employees' Service (Amendment) Regulations, 1987.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the All-India Employees' Service Regulations 1963 (hercinafter referred to as the said Regulations), for the existing Regulation 48, the following Regulation shall be substituted:—
  - (a) The services of a permanent employee may be terminated without assigning any reasons to him/ber and without any prior notice but only on the following grounds not amounting to misconduct under Service Regulation 42, namely:—
    - (i) if he/she is, in the opinion of the Corporation (the Board of Directors of Air-India) incompetent and unsuitable for continued employment with the Corporation and such incompetence and unsuitability is such as to make his/her continuance in employment detrimental to the interests of the Corporation;

OR

if his/her continuance in employment constitutes, in the opinion of the Corporation (the Board of Directors of Air-India), a grave security risk making his/her continuance in service detrimental to the interests of the Corporation;

OR

if, in the opinion of the Corporation (the Board of Directors of Air-India), there is such a justifiable lack of confidence which, having regard to the nature of duties performed, would make it necessary, in the interest of the Corporation, to immediately terminate his/her services.

- (b) The services of an employee on probation may be terminated without assigning any reason to him/ her but on giving 30 days notice in writing or pay in lieu thereof.
- (c) he services of a temporary employee may be terminated without assigning any reasons to him/her but on giving 15 days notice in writing or pay in lieu therof.

Explanation: For the purpose of this Regulation, the word 'pay' shall include all emoluments which would be admissible if he were on privilege leave.

- 3. In the said Regulations after Regulation 44, the following Regulation shall lbe added namely:—
  - 44(Λ) (i) Notwithstanding anything contained in these Regulations and if, in the opinion of the Corporation (the Board of Directors of Air-India).

it is not possible or practicable to hold an enquiry under the relevant provisions of these Regulations, the Corporation may, if satisfied that the the employee has been guilty of any act of misconduct, impose in respect of such misconduct, any one of the punishments mentioned in Regulation 43 on the employee concerned.

Provided that before exercising this extraordinary power, the Board shall give 30 days prior notice to the employee concerned of the act of misconduct and the reasons why it is not possible or practicable to hold an enquiry into such misconduct, and the punishment proposed by the Board, and the employee shall be entitled to make a full written representation to the Board in response to such notice

(ii) No action shall be taken under this Regulation until the Board has taken into consideration the representation made by the concerned employee under the priviso to section (i) within the notice period.

Note: Pirncipal Regulation published vide Notification dated 19-10-1963.

Gazette of India 1963, Part III, Section IV, Pages 636 & 637.

S. NARAYANSWAMY, Secy.